संख्या-27/2026/873/सत्रह-म-2026-17-1099/11/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिंनाक 26 मई, 2026

विषयः प्रदेश में डिजिटल तकनीकी के उपयोग से जलीय संसाधनों का डिजिटल सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-295/नि0शा0/ दिशा- निर्देश/ 2026-27 दिनांक 07.05.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में डिजिटल तकनीकी के उपयोग से जलीय संसाधनों का डिजिटल सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता योजना को सम्यक विचारोपरान्त क्रियान्वयन/संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- प्रदेश में डिजिटल तकनीकी के उपयोग से जलीय संसाधनों का डिजिटल सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा- निर्देश निम्नवत हैं-

योजना के दिशा-निर्देश

1.योजना का उद्देश्यः-

मत्स्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी के उपयोग, प्रौद्योगिकी विस्तार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जल स्रोतों यथा तालाब, नदियाँ, जलाशय का डिजिटल सर्वे और GIS आधारित मानचित्रण, वाटर क्वालिटी डेटा मॉडल, और वैज्ञानिक मत्स्य पालनके लिए sensor/IoT आधारित real-time प्रबंधन के उदेश्य से यह योजना संचालित की जानी है। योजना के माध्यम से जल गुणवत्ता एवं जल उपलब्धता के डेटा का संग्रह, विश्लेषण, वैज्ञानिक विधि से जल पैरामीटर का परीक्षण तथा मत्स्य पालन के लिए उपयुक्तता निर्धारण के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना एवं रोज़गार सृजन और मत्स्य पालकों को अधिकतम लाभ प्रदान करना सम्मिलित होगा ।

उत्तर प्रदेश के मत्स्य क्षेत्र में डिजिटल तकनीकी के उपयोग से जलीय संसाधनों का डिजिटल सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता से मछुआरों, मत्स्य पालकों, प्रसंस्करणकर्ताओं और अन्य हितधारकों तक बेहतर प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने और बढ़ावा देने में सहयोग प्रदान किया जा सकेगा। मत्स्य हार्वेस्टिंग में नवीन तकनीकों के उपयोग से मूल्यवर्धन और बाजार तक (real time monitoring/ marketing facilities) पहुंच को बढ़ावा मिलेगा।

2. योजना का औचित्य

वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मत्स्य उत्पादन 13.31 लाख टन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल 18.56 लाख टन के साथ देश में द्वितीय स्थान पर है। प्रदेश में जलीय संसाधनों का डिजिटल सर्वे एवं मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी की उपयोगिता अति आवश्यक है, भारत तथा उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं प्रसार तेजी से हो रहा है। विशेष रूप से आधुनिक उपकरणों, डेटा-आधारित प्रणालियों और अनुसंधान-समर्थित प्रणालियों के उपयोग से उत्पादन, प्रबंधन, आधुनिक विपणन, रियल टाइम मोनिट्रिंग, मार्केट प्रबंधन तथा मत्स्य पालकों को आर्थिक लाभ पहुचाने में सततता में सुधार हुआ है। मत्स्य पालन अब पारंपरिक तरीकों से आधुनिक तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। IOT एवं सेंसर आधारित निगरानी से पानी की गुणवत्ता (pH, DO, टेम्परेचर आदि) रियल-टाइम मॉनीटरिंग तथा इसके आधार पर एरिया विशेष मत्स्य प्रजातियों का चयन करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र को चिन्हित करते हुए मत्स्य गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना वर्तमान की आवश्यकता है। इस योजना के माध्यम से डेटा विश्लेषण, ड्रोन तकनीकी, AI एवं रीमोट सेन्सिंग के माध्यम से मत्स्य पालन, फीडिंग प्रबंधन, जलीय संसाधनों का सर्वे होने से प्रदेश के भौगोलिक जलीय विशेषताओं के आधार पर मत्स्य क्षेत्र के विकास में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी ।

3.योजना का कार्यान्वयन –

यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से आगामी 03 वर्ष हेतु संचालित की जानी है। शासन द्वारा नियमानुसार ई-निविदा आदि की कार्यवाही कराते हुए संस्था का चयन किया जाएगा। चयनित संस्था के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में उपलब्ध जल संसाधनों का डिजिटल सर्वे कराकर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर समस्त जलीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना है। योजनान्तर्गत आधुनिक उपकरणों, डेटा-आधारित प्रणालियों और अनुसंधान-समर्थित प्रणालियों का उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन, प्रबंधन, आधुनिक विपणन, रियल टाइम मोनिट्रिंग, मार्केट अब पारंपरिक तरीकों के स्थान पर आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किया जाना है। IOT एवं सेंसर आधारित निगरानी से पानी की गुणवत्ता (pH, DO, टेम्परेचर आदि) की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी। IOT एवं सेंसर आधारित निगरानी से पानी की गुणवत्ता हेतु निश्चित क्षेत्र में सर्वे किया जाएगा तथा लगभग 5 प्रतिशत उपयुक्त क्षेत्र में उक्त की स्थापना हेतु संस्तुति प्रदान करनी होगी। प्रथम चरण में IOT एवं सेन्सर की स्थापना विभागीय क्रियाशील 35 प्रक्षेत्रों पर किया जाना उचित होगा। इस योजना के माध्यम से डेटा विश्लेषण, ड्रोन तकनीकी, AI एवं रीमोट सेन्सिंग के माध्यम से मत्स्य पालन, फीडिंग प्रबंधन, जलीय संसाधनों का सर्वे होने से प्रदेश के भौगोलिक जलीय विशेषताओं के आधार पर मत्स्य क्षेत्र के विकास में अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी ।

3.1 योजनान्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियां-

- डिजिटल तालाब सूची और परिसंपत्ति मानचित्रण । जल क्षमता का अनुमान। सैटेलाइट बेसलाइन और जीआईएस मैपिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी स्थिर जल भंडारों की पहचान करना और जिलावार सूची तैयार करना
- मछली पकड़ने के उद्देश्य से पट्टे पर दिए गए जिलेवार तालाबों की सूची और इस उद्देश्य

के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य जल निकायों की सूची प्रस्तुत करना।

- द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर जल निकायों के जिलावार उपयोग का विश्लेषण करना।
- वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों का उपयोग करके सभी जल निकायों के उपयोग के संबंध में जिलावार प्राथमिक डेटा एकत्र करना। नमूने मुख्य रूप से 0.2 हेक्टेयर या उससे बड़े जल निकायों से लिए जाने चाहिए।
- भूमि अभिलेख, पट्टा प्रबंधन, राजस्व ट्रैकिंग और पट्टा एकीकरण
- जमीनी सत्यता और क्षेत्र सत्यापन
- जल विज्ञान एवं क्षमता मॉडलिंग
- आईओटी-आधारित जल गुणवत्ता निगरानी:

मद	गतिविधियाँ
जल गुणवत्ता पैरामीटर	pH, DO, TDS, Temperature, salinity, आदि
स्थलीय जानकारी	GPS + GIS मैपिंग
उत्पादन डाटा	प्रजाति वार मत्स्य उत्पादन , मत्स्य बीज आदि
पर्यावरणीय डाटा	मौसम, वर्षा डेटा, सीज़नल वैरिएशन
विपणन डाटा	real time प्राइस इनफार्मेशन, मंडी सूचना, डिजिटल मार्केटिंग आदि।
तालाब प्रबंधन	ड्रोन तकनीकी, तकनीकी आधारित फीडिंग, रोग प्रबंधन आदि
मोबाइल/वेब पोर्टल	क्षेत्रीय मत्स्य अधिकारियों एवं मत्स्य पालकों द्वारा गतिविधियों का अनलाइन डाटा फीडिंग

- बाजार मानचित्रण और मूल्य निर्धारण संबंधी जानकारी। थोक और खुदरा मछली बिक्री केंद्रों का अध्ययन करके किस्मवार मछली उत्पादन और उनके खुदरा मूल्यों की पहचान करना।
- आधिकारिक तौर पर घोषित कीमतों और थोक विक्रेताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए प्राप्त वास्तविक कीमतों में अंतर का पता लगाना।
- राज्य में सजावटी मछलियों के जिलावार उत्पादन और उनके प्रचलित बाजार मूल्यों की पहचान करना।
- राज्य में मछली पकड़ने के उद्देश्यों के लिए जल निकायों के उपयोग में आने वाली चुनौतियों का आकलन करना और वास्तविक मछली उत्पादन/मूल्य डेटा प्राप्त करना तथा संभावित विकास के अवसरों की पहचान करना।
- राज्य में मछली उत्पादन गतिविधि को बढ़ाने और उत्तर प्रदेश के सकल लाभ मूल्य (जीवीए) को बढ़ावा देने में इसकी आर्थिक भूमिका को बढ़ाने के लिए अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना।
- यह आकलन करना कि अध्ययन एवं सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग जी.वी.ए./जी.एस.वी.ए./जी.डी.पी. अनुमान में कैसे किया जाएगा।
- राज्य में अंतर्देशीय मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए जल निकायों के इष्टतम उपयोग द्वारा

राज्य के सकल लाभ मूल्य (GVA) और जीडीपी में मूल्यवर्धन का अनुमान लगाने के लिए प्रॉक्सी संकेतकों की पहचान करना।

- विभाग द्वारा पहले से ही लागू की जा रही सभी केंद्र/राज्य सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से फील्ड सत्यापन। डेटा संग्रह के लिए एक ऐप विकसित किया जाएगा, जिसमें किसानों का संपादन योग्य प्रारूप में ऑनलाइन डेटाबेस/फ्रेम भी शामिल होगा, ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके।
- AI-आधारित Threshold मॉनिटरिंग। नवीनतम एआई तकनीक का उपयोग करते हुए राज्य में मछली पकड़ने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा रहे/उपयोग किए जा सकने वाले सभी जल निकायों की जिलावार विस्तृत सूची के साथ एक integrated डैशबोर्ड बनाना।
- डेटा इनपुट, प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स, कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक बैकएंड प्लेटफॉर्म विकसित करना।
- संस्थागत परिसंपत्ति एवं प्रशिक्षण प्रबंधन
- भूलेख & लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेशन
- वास्तविक समय में जल गुणवत्ता संबंधी जानकारी
- निरंतर डेटा प्रसारण
- पूर्वानुमानित जोखिम विश्लेषण
- मत्स्य परिसंपत्तियों का खाता बही और स्टॉक ट्रैकिंग
- फिश हार्वेस्टिंग के समय प्रविष्टि और उपज का रिकॉर्ड रखना
- उत्पादकता सूचकांक की गणना
- विभाग का एवं विभाग से संबंधित अन्य विभागों का इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड तैयार करना
- योजनान्तर्गत उल्लिखित उक्त गतिविधियों के अतिरिक्त योजना से संबंधित ToR के अन्य बिन्दु आवश्यकता के दृष्टिगत विचार विमर्श के उपरांत सर्वे हेतु बाद में भी जोड़े जा सकते हैं।

4. अनुमानित लागत एवं वित्त पोषण

यह शत-प्रतिशत राज्य पोषित परियोजना है।योजना का कुल बजट रु० 306.00 लाख है। वर्ष 2026-27 हेतु योजना अंतर्गत प्रथम चरण में निर्धारित गतिविधियों/ कार्यक्रमों आदि के स्थापना हेतु रु० 150.00 लाख वित्तीय प्रावधानित हैं।

5. योजना प्रबंधन, निगरानी और पर्यवेक्षण

5.1 योजनान्तर्गत के क्रियान्वयन हेतु कार्यादायी संस्था का चयन मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मत्स्य – अध्यक्ष

(2) महानिदेशक मत्स्य – सदस्य

(3) निदेशक मत्स्य – सदस्य

(4) संयुक्त निदेशक मत्स्य – सदस्य

(5) उप निदेशक सांख्यिकी- सदस्य सचिव

5.2 योजनान्तर्गत गतिविधियों की निगरानी, सफल कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन हेतु मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश फील्ड स्तर से महानिदेशक मत्स्य की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक राज्य स्तरीय फील्ड निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

(1) महानिदेशक मत्स्य – अध्यक्ष

(2) निदेशक मत्स्य – सदस्य

(3) संयुक्त निदेशक मत्स्य – सदस्य

(4) मंडलीय उपनिदेशक मत्स्य – सदस्य सचिव

(5) सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य

(6) परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति

(7) त्रैमासिक रूप से एक बार बैठक करेगी।

(8) राज्य स्तरीय निगरानी समिति, जनपदीय अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यक मार्गदर्शन एवं सलाह देगी।

6. योजना से अपेक्षित परिणाम

- उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन व संचालन से प्रदेश की मात्स्यकी क्षेत्र में डिजिटल क्रांति आएगी जिसके फलस्वरूप मत्स्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि आएगी।
- योजना के क्रियान्वयन से सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही मत्स्य विभाग से संबंधित समस्त आंकड़ों को संकलित एवं प्रदर्शित किया जा सकेगा जिससे एक क्लिक से जन सामान्य को समस्त मत्स्य गतिविधियों से संबंधित सूचना प्राप्त हो सकेंगी साथ ही इन्वेस्टर्स को प्रदेश में मत्स्य क्षेत्र में इनवेस्टमेंट हेतु आकर्षित किया जा सकेगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, वैज्ञानिक पैरामीटर पर आधारित प्रबंधन से उत्पादन सुधार, GPS/Drone आधारित जल स्रोत मैपिंग, GIS सिस्टम में तालाब, नहर, जलाशयों के सीमांकन, मोबाइल ऐप/सेंसर से रियल-टाइम पानी की गुणवत्ता (pH, DO, TDS, salinity, hardness आदि) का डेटा, डेटाबेस + क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डेटा संग्रह, AI/ML मॉडल से ट्रेंड विश्लेषण, यह योजना मत्स्य संसाधनों एवं उत्पादन के वैज्ञानिक प्रबंधन, सही ट्रेंड/पूर्वानुमान और नीति निर्णयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
- IoT सेंसर्स और मोबाइल डेटा लॉगिंग से जल पैरामीटर का real time निरीक्षण संभव हो सकेगा। जिससे मत्स्य पालन को वैज्ञानिक रूप में नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे AI/ML आधारित फीड शेड्यूलिंग और early-warning अलर्ट सिस्टम, साथ ही मत्स्य क्षेत्र के आधुनिकरण से संसाधनों का समुचित उपयोग होने से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस काम होगा, उद्यमिता का विकास होने से प्रदेश की वन ट्रिलियन

डॉलर अर्थव्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के प्रस्तावित लक्ष्यों को मत्स्य पालन विभाग के वर्तमान GSVA 22,000 करोड़ से मार्च 2028 तक 45,000 करोड़, मार्च 2030 तक 55,000 करोड़ एवं मार्च 2047 तक 1.20 लाख करोड़ GSVA प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।
कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 23-05-2026 15:46:00

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 27 /2026 /873(1) / सत्रह-म-2026 तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रसस्करण / राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।